

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ७ सन् २०१६

मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, २०१६

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) अधिनियम, २०१६ है.

संक्षिप्त नाम.

भाग-एक

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) का संशोधन

२. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) में, धारा १३३-क में, उपधारा (१) में,—

मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक २३ सन्
१९५६ का संशोधन.

(एक) शब्द "एक प्रतिशत" के स्थान पर, शब्द "दो प्रतिशत" स्थापित किए जाएं.

(दो) निम्नलिखित उपबंध जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"नगरपालिक निगम को इस प्रकार प्राप्त होने वाली शुल्क की राशि का उपयोग अधोसंरचना विकास की परियोजनाओं को क्रियान्वित करने में अथवा ऐसी परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए संबंधित नगरपालिक निगम द्वारा अथवा उसकी ओर से लिए गए ऋणों का प्रतिसंदाय करने में किया जाएगा."

भाग-दो

मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) का संशोधन

३. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) में, धारा १६१ में, उपधारा (१) के आरंभिक पैरा में,—

मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक ३७ सन्
१९६१ का संशोधन.

(एक) शब्द "एक प्रतिशत" के स्थान पर, शब्द "दो प्रतिशत" स्थापित किए जाएं.

(दो) कोलन के स्थान पर पूर्ण विराम स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित उपबंध जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"नगरपालिका परिषद् या नगर परिषद् को इस प्रकार प्राप्त होने वाली शुल्क की राशि का उपयोग अधोसंरचना विकास की परियोजनाओं को क्रियान्वित करने में अथवा ऐसी परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए संबंधित नगरपालिका परिषद् या नगर परिषद् द्वारा अथवा उसकी ओर से लिए गए ऋणों का प्रतिसंदाय करने में किया जाएगा."

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राज्य में बढ़ते हुए शहरीकरण को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि भारत सरकार और राज्य की नगरीय विकास और अधोसंरचना की महत्वपूर्ण योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए नगरीय स्थानीय निकायों को वित्तीय रूप से सुदृढ़ किया जाए. स्टाम्प शुल्क प्रभार राज्य में नगरीय स्थानीय निकायों को आवंटन का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मद है. वर्तमान में नगरीय स्थानीय निकाय सम्पत्ति के मूल्य का एक प्रतिशत स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर रहे हैं. राज्य सरकार ने स्टाम्प शुल्क प्रभार एक प्रतिशत से बढ़ाकर दो प्रतिशत करने का विनिश्चय किया है. इस आवंटन का उपयोग महत्वपूर्ण नगरीय अधोसंरचना योजनाओं जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन, अमृत स्मार्ट सिटी, मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास, मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजनाओं आदि को क्रियान्वित करने में अथवा ऐसी परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए संबंधित नगरीय निकाय द्वारा अथवा उसकी ओर से लिए गए ऋणों का प्रतिसंदाय करने में किया जाएगा.

उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने की दृष्टि से मध्यप्रदेश नगरपालिका निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) की धारा १३३-क और मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) की धारा १६१ में यथोचित संशोधन प्रस्तावित है.

अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
दिनांक २९ मार्च, २०१६.

शिवराज सिंह चौहान
भारसाधक सदस्य.

“संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.”

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

उपाबंध

भाग-एक

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ विधि (संशोधन) विधेयक, २०१६
(क्रमांक २३ सन् १९५६) से उद्धरण.

* * * * *

धारा १३३-क (१) भारतीय स्टॉम्प अधिनियम, १८९९ (१८९९ का सं. २) द्वारा स्थावर सम्पत्ति के क्रमशः विक्रय दान तथा भोग बंधक की लिखतों पर अधिरोपित शुल्क में उन लिखतों की दशा में जो किसी निगम की सीमाओं के भीतर स्थित स्थावर सम्पत्ति को प्रभावित करती है और उस तारीख को या उसके पश्चात् निष्पादित की गई है जिसको इस अधिनियम के उपबंध ऐसी सीमाओं को लागू किये जाते हैं, ऐसी स्थिति सम्पत्ति के मूल्य पर या भोग बंधक की दशा में, लिखित द्वारा प्रतिभूत उस रकम पर जो लिखित में उपवर्णित है, एक प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी.

* * * * *

भाग-दो

मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) से उद्धरण.

* * * * *

धारा १६१ (१) भारतीय स्टॉम्प अधिनियम, १८९९ (१८९९ का सं. २) द्वारा स्थावर सम्पत्ति के क्रमशः विक्रय दान तथा भोग बंधक की लिखतों पर अधिरोपित शुल्क में उन लिखतों की दशा में जो किसी नगरपालिका की सीमाओं के भीतर स्थित स्थावर सम्पत्ति को प्रभावित करती है और उस तारीख को या उसके पश्चात् निष्पादित की गई है जिसको इस अधिनियम के उपबंध उस नगरपालिका में प्रवृत्त होते हैं, ऐसी स्थिति सम्पत्ति के मूल्य पर या भोग बंधक की दशा में, लिखित द्वारा प्रतिभूत उस रकम पर जो लिखित में उपवर्णित है, एक प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी.

* * * * *

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.